RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 296
दि. 27.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत और इजरायल जल्द करेंगे फ्री ट्रेड डील, आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं, बोले पीएम मोदी

(जीएनएस)।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 फरवरी को दो दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं। वे इजरायली समय के अनुसार दोपहर 12.45 बजे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इजरायल के संबंधों पर बात की। दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी ने साझा बयान जारी किया है।

यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है। इससे पहले वह 2017 में भी इजरायल गए थे। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते मंत्री हैं, जिन्होंने इजरायल का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत-इजरायल के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी में हुई तरक्की की समीक्षा की है। दोनों नेताओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत पीपुल-टू-पीपुल सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'याद वाशेम' में होलोकॉस्ट पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति हर्जोग संग लगाया 'एक पेड़ मां के नाम'

यरूशलम, 26 फरवरी (आईएएनएस)। इजरायल दौरे के दूसरे दिन, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'याद वाशेम' पहुंचे। नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद प्रेसिडेंशियल गार्डन में राष्ट्रपति हर्जोग के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' लगाया।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट पर इसे नरसंहार के पीड़ितों को दिया गया सम्मान बताया।

उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर, याद वाशेम का दौरा किया। यह पीएम का याद वाशेम का दूसरा दौरा था। पीएम ने होलोकॉस्ट पीड़ितों को फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने दिल को छू लेने वाले बुक ऑफ नेम्स हॉल का भी दौरा किया, जो होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए लाखों लोगों की याद को सहेजे हुए है।"

पोस्ट के अनुसार, यह मेमोरियल अतीत की क्रूरता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर दुनिया बनाने के हमारे मिलकर किए गए इरादे की याद दिलाता है।

प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव राष्ट्रपति हर्जोग से मुलाकात थी।

प्रधानमंत्री 27 फरवरी को 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त' विषय पर बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 फरवरी को प्रातः लगभग 11:30 बजे 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त' विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, अवसंरचना विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की संरचना को सुदृढ़ करने, पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने तथा कर सुधारों के माध्यम से नागरिकों के जीवनयापन को अधिक सरल और सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2026-27 से उभरने वाले प्रमुख विषयों पर आयोजित किये जा रहे बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला में पहला है। इन वेबिनारों का उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीख लेना और प्रतिभागियों से संरचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना है ताकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन को सुदृढ़ और सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें विभिन्न हितधारकों के व्यावहारिक अनुभव और अंतर्दृष्टि का लाभ उठाया जा सके। इनमें उद्योग, वित्तीय संस्थानों, बाजार प्रतिभागियों, सरकार, उद्योग नियामकों और शिक्षा जगत के हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा ताकि प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन मार्गों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

28 फरवरी से दो दिन के तमिलनाडु-पुदुचेरी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जानें पूरा कार्यक्रम

नई दिल्ली, (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को दो दिवसीय दौरे के लिए तमिलनाडु जाएंगे, जहां वे चेन्नई, मदुरै और पुदुचेरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे मदुरै में एम्स का उद्घाटन करेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री शनिवार शाम को चेन्नई पहुंचेंगे और राजभवन में ठहरेंगे। 1 मार्च को वे पुदुचेरी जाएंगे, जहां वे एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पुदुचेरी में अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद, प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मदुरै के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वे तिरुप्पारनकुंड्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, जो भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवासों में से एक है और तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है।

एम्स का करेंगे उद्घाटन

मदुरै में प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। यह दौरा दक्षिणी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के विस्तार और विकास पहलों में तेजी लाने पर केंद्र के फोकस को रेखांकित करता है रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मदुरै में एक सरकारी समारोह के दौरान दक्षिणी रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, मोराप्पुर, बोम्मिडी, पोलाची, कराईकुडी, श्रीविल्लिपुथुर, चोलावंदन, तिरुवरूर और मनप्पराई में नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया

(जीएनएस)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (26 फरवरी, 2026) झारखंड में जमशेदपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इसका आयोजन श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट, जमशेदपुर ने किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी कृपा बिना किसी भेदभाव के समस्त मानव जाति पर समान रूप से बरसती है।

'साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0' के विजेताओं का सम्मान

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने आज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल 'साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0' (जीएसजीसी 2.0) के विजेताओं को सम्मानित किया। यह पहल भारत में डेटा संरक्षण पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। इस पहल का उद्देश्य देश की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ डिजिटल तंत्र को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता का निर्माण करना है।

साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 में कुल 6.85 करोड़ रुपये का पुरस्कार पूल था जिससे यह देश में सरकार द्वारा समर्थित सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौतियों में से एक बन गया। ग्रैंड चैलेंज 2.0 के विजेताओं को ट्रॉफी और एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि प्रथम और द्वितीय उपविजेताओं को क्रमशः 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये प्राप्त हुए।

विजेताओं की सूची और उनके द्वारा हल की गई समस्याएं इस प्रकार हैं:

स्टार्ट-अप : समस्या विवरण का समाधानविजेता, कैम्ब्रियन स्किल्सडा टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी (सीएसटीसीएस), अगली पीढ़ी के बायोमेट्रिक सिस्टम को सुरक्षित करना, प्रथम उपविजेता, क्रिप्सिस, क्लोन और नकली ऐप्स से बचाव

द्वितीय उपविजेता

जिरिजडॉटएआई, एपीआई सुरक्षा

जनवरी 2025 में माईगव प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई साइबर

सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित कर हमारे देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन क्षेत्रों में एपीआई सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, पहनने योग्य उपकरणों की सुरक्षा और गोपनीयता, क्लोन और नकली ऐप का निवारण, खतरे का पता लगाने और घटना प्रतिक्रिया के लिए एआई, और अगली पीढ़ी के बायोमेट्रिक सिस्टम को सुरक्षित करना शामिल है। इस पहल की एक अनूठी विशेषता यह है कि विकसित समाधानों के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधित स्टार्ट-अप के पास हैं।

यह चैलेंज चार व्यवस्थित चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्तर पर क्रमिक मूल्यांकन और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आइडिया स्टेज में, प्रत्येक समस्या विवरण के तहत छह स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया, जिससे कुल 36 स्टार्ट-अप्स हो गए और प्रत्येक को अपने समाधानों को और विकसित और परिष्कृत करने के लिए पांच लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।

न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन चरण के दौरान इन स्टार्ट-अप्स को कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने के लिए व्यवस्थित तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसके बाद 18 स्टार्ट-अप्स (प्रत्येक समस्या विवरण के तहत तीन) अंतिम उत्पाद चरण में पहुंचे और प्रत्येक को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। इस चरण में समाधानों का परीक्षण और सत्यापन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पांच स्टार्ट-अप्स का चयन हुआ और प्रत्येक को 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। अंतिम गो-टू-मार्केट स्टेज में स्टार्ट-अप्स का मूल्यांकन व्यावसायिक तत्परता मापनीयता और बाजार क्षमता के आधार पर किया गया और तीन स्टार्ट-अप्स को शीर्ष विजेता घोषित किया गया। पूरे चैलेंज के दौरान भाग लेने वाले स्टार्ट-अप्स को उत्पाद की परिपक्वता, तैनाती क्षमता और बाजार तत्परता को मजबूत करने के लिए निरंतर तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

एमईआईटीवाई के सचिव श्री एस. कृष्णन ने कहा, 'साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 देश में मजबूत स्वदेशी साइबर सुरक्षा क्षमता के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साइबर सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां घरेलू क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा में स्वदेशीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियां वास्तविक और लगातार बदलती रहती हैं, और हमें अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकसित समाधानों के साथ तैयार रहना चाहिए।'

इस चैलेंज के लिए एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है, और इसमें छात्रों के नेतृत्व वाली टीमों, स्टार्ट-अप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों सहित व्यापक भागीदारी देखकर उत्साहजनक है। समस्या विवरण सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे और आज की डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं, जहां एपीआई जैसे तंत्रों के माध्यम से डेटा साझाकरण में वृद्धि के साथ-साथ मजबूत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षा उपायों का होना आवश्यक है। यह पहल दीर्घकालिक घरेलू क्षमता निर्माण को जारी रखने का एक अवसर है और हमें भविष्य में भी इस गति को बनाए रखना होगा। एमईआईटीवाई साइबर सुरक्षा में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और

भारत की अंतरिक्ष प्रणाली को मिली साइबर सुरक्षा

(जीएनएस)।

अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा भारत की अंतरिक्ष वास्तुकला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सुरक्षा में उपग्रह संचार प्रणाली भी शामिल है। ये प्रणालियां दूरस्थ और कार्यनीतिक क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में सहयोग करती हैं, आपदा राहत तंत्र को मजबूत करती हैं, नौवहन और प्रसारण सेवाओं को सुगम बनाती हैं, और राष्ट्र के विकास तथा उसकी सुदृढ़ता के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आधार प्रदान करती हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने एसआईए-इंडिया के सहयोग से अंतरिक्ष संचार संपत्तियों की सुरक्षा और भारत की अंतरिक्ष प्रणाली की मजबूती में योगदान देने के लिए अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा हेतु एक व्यापक ढांचा और दिशा-निर्देश विकसित किए हैं। ये दिशा-निर्देश 24-26 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित डेफसैट सम्मेलन और एक्सपो-2026 के दौरान जारी किए गए।

ये दिशा-निर्देश परामर्शात्मक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ावा देना है। इस ढांचे को अंतरिक्ष प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के सहयोग से तैयार किया गया है। इन हितधारकों में सरकारी एजेंसियां, उपग्रह सेवा प्रदाता, ग्राउंड स्टेशन संचालक, उपकरण विक्रेता और निजी अंतरिक्ष उद्यम शामिल हैं।

आवश्यक साइबर सुरक्षा सिद्धांतों, अनुशंसित नियंत्रणों और स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों को स्पष्ट करके ये दिशा-निर्देश पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में सुदृढ़ता, जवाबदेही और सक्रिय जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देंगे।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने कहा, 'सीईआरटी-इन भारत के सभी क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की प्रौद्योगिकी संप्रभुता और भविष्य के विकास के लिए उपग्रह संचार नेटवर्क सहित अंतरिक्ष प्रणालियों के कार्यनीतिक महत्व को पहचानते हुए ये व्यापक दिशानिर्देश गहन, व्यापक और उच्च स्तरीय सुरक्षा उपायों पर विचार कर एक एकीकृत और दूरदर्शी ढांचा स्थापित करते हैं, ताकि तेजी से विकसित हो रहे और अधिक परिष्कृत होते साइबर खतरों से उपग्रह नेटवर्क, जमीनी बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष संबंधी आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा की जा सके।'

एसआईए-इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सुब्बा राव पावुलुरी ने कहा, 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी और उद्योग जगत के सुविचारित राय किसी भी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मूलभूत हैं। सीईआरटी-इन और एसआईए इंडिया का यह संयुक्त दिशा-निर्देश दस्तावेज एक समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें उद्योग जगत के दृष्टिकोण को सीईआरटी-इन की गहन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता के साथ एकीकृत किया गया है। ये दोनों मिलकर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की साइबर सुरक्षा को आगे बढ़ाने और उभरते डिजिटल खतरों से निपटने की इसकी तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।'

एसआईए-इंडिया के महानिदेशक श्री अनिल प्रकाश ने कहा, ' भारत के बढ़ते अंतरिक्ष परितंत्र के लिए अब साइबर सुरक्षा को एक तकनीकी पहलू से हटकर मिशन सुरक्षा का एक मुख्य स्तंभ बनाना आवश्यक है। सीईआरटी-इन के साथ विकसित संयुक्त ढांचा उपग्रहों, जमीनी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूती को संस्थागत रूप देता है—विशेष रूप से ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15 लाख से अधिक साइबर हमले के प्रयास दर्ज किए गए और सरकारी नेटवर्क पर हमले लगभग सात गुना बढ़ गए। इस बदलते खतरे के परिदृश्य में, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और उद्योग समान रूप से असुरक्षित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये साइबर दिशा-निर्देश एक अनुकूलनीय मॉडल पर आधारित हैं और उभरते खतरों तथा तकनीकी प्रगति के प्रति उत्तरदायी बने रहने के लिए संरचित उद्योग परामर्श के माध्यम से समय-समय पर परिष्कृत किए जाएंगे।

उप-राष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महिलाओं का प्रदर्शन सराहनीयः उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने स्नातकों से

अनुकूलन और नवाचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर तत्व है

कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का आ'नः 'यह हम सबका कश्मीर है'

दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का मूल आधार है: उपराष्ट्रपति

चुंगथांग-लाचेन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन

(जीएनएस)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उत्तरी सिक्किम में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पुनर्निर्मित चुंगथांग-लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन ताराम चू पुल का उद्घाटन किया। यह मई-जून 2025 में विनाशकारी बादल विस्फोट, जून 2024 में चक्रवात रेमल और अक्टूबर 2023 में हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ के बाद सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा किए जा रहे आपदा राहत प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सीमा सुरक्षा संगठन ने संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए, स्वास्तिक परियोजना के तहत 96 भूस्खलनों को साफ किया, चार प्रमुख पुलों का निर्माण किया और दो अन्य पुलों की मरम्मत की। सीमा सुरक्षा संगठन की इंजीनियरिंग टीम ने 8 किलोमीटर की नई भू-सफाई पूरी की और अस्थिर ढलानों और धंसने वाले क्षेत्रों से निकलने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग बनाए। ये प्रयास अक्टूबर 2025 में 7.5 किलोमीटर लंबे नागा-टूंग मार्ग के खुलने के बाद किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में संपर्क और मजबूत हुआ है। 28 किलोमीटर लंबी चुंगथांग-लाचेन सड़क और ताराम चू पुल के पूरा होने से स्थानीय निवासियों, सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये परिसंपत्तियां उत्तरी सिक्किम के बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। इन महत्वपूर्ण सड़क संपर्क सुविधाओं का उद्घाटन सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा उल्लिखित 'आत्मनिर्भर सिक्किम-विकसित भारत विजन' के अनुरूप है।

सम्पादकीय

ईरान में रमजान को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमले की लगातार धमकियों के बीच ईरान में रमजान को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टो के अनुसार ईरान के भीतर सार्वजनिक जीवन नियमित रूप से चल रहा है। उधर ईरान से सटे इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती तैनाती अब सिर्प संकेत देने तक सीमित नहीं लगती बल्कि ये वास्तविक जंग के स्पष्ट संकेत हैं। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहिम लिंकन और यूएसएस फोर्ड के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा सैकड़ों अमेरिकी फाइटर जेट व अन्य साजोसामान भी इस इलाके में पिछले वुछ दिनों में लाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका-इजराइल यहां कई स्तरों पर सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहे हैं। ईरान में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। जंग की आहट के बावजूद ईरान में सब सामान्य दिख रहा है। मस्जिदों में विशेष नमाज, बड़े इफ्तार आयोजन और सदका-फितर प्रमुखता से हो रही है। इस्लामिक रिपब्लिकन न्यूज एजेंसी ने रमजान के अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का संदेश प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने इस महीनों को आत्मचिंतन और एकजुटता का समय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की शक्तियां हमें अपना सिर झुकाने के लिए साजिश कर रही हैं.. लेकिन वे हमारे लिए जो भी समस्याएं पैदा करें, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इससे पश्चिम एशिया में एक क्षेत्रीय (रीजनल) युद्ध छिड़ सकता है, तनाव और अधिक बढ़ सकता है। खामनेई ने कहा कि ईरान उकसाने की नीति नहीं अपनाता लेकिन उन्होंने साफ किया कि ईरानी राष्ट्र पर अगर कोई हमला या उत्पीड़न किया गया तो ईरान ऐसा कड़ा जवाब देगा जिसका अमेरिका-इजराइल को अंदाजा नहीं। हम पर कोई भी स्ट्राइक हो चाहे वह लिमिटेड स्ट्राइक ही क्यों न हो पर उसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। मध्यपूर्व के तमाम अमेरिकी सैन्य बेसों सहित उनके युद्धपोत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार अपनी शर्ते बदल रहे हैं। पहले उन्होंने तीन शर्ते रखी थीं: ईरान अपना परमाणु कार्यंव्रम खत्म करे, अपनी मिसाइलों की प्रोडक्शन और क्षमता कम करे। ईरान से अमेरिका की इस सिलसिले में दो बार जेनेवा में वार्ता विफल हो चुकी है। अब तीसरे और अंतिम राउंड की बात हो रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से बेहतर वुछ हो ही नहीं सकता। अमेरिका इन तरीकों से ईरान को घेरने की युद्ध नीति पर काम कर रहा है। जंगी जहाजों की तैनाती, अरब सागर में तैनात अमेरिका के विशाल विमान वाहक पोतों को घेरने की है। पहले बड़ी संख्या में टैंक से जहाजों के सुरक्षा सिस्टम को उलझाएंगे, ताकि वे मिसाइल को रोकने में कामयाब रहें। दूसरीः खाड़ी देशों के मौजूद अमेरिका के 19 ठिकानों पर करीब 50, 000 सैनिक किसी भी समय हमले में भाग ले सकते हैं। हालांकि यही सैनिक ईरान के निशाने पर होंगे। तीसरीः तेल सप्लाई रोकना। अमेरिका इस प्रयास में है कि ईरान किसी भी देश को अपने यहां से तेल सप्लाई न कर सके ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़े। उसने भारत पर भी दबाव डाला है कि भारत ईरान से तेल लेना बंद करे। इस बीच इजराइल से एक अपुष्ट खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि इजराइल ने अब चेतावनी दी है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो वह ऐसे हथियार चलाएगा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। इशारा साफ है कि परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। वुल मिलाकर बड़ी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। उम्मीद की जाती है कि जंग टले क्योंकि अगर यह होती है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है।

पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट परियोजना शुरू

केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट परियोजना शुरू किया

पुडुचेरी में लाभार्थियों के पारंपरिक बैंक खातों के बजाय सीबीडीसी वॉलेट में खाद्य सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण किया जाएगा, यहाँ वर्तमान में डीबीटी मॉडल के माध्यम से पीडीएस लागू किया जा रहा है

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सीबीडीसी का एकीकरण पारदर्शी और सशक्त खाद्य वितरण प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

'हर दाना, हर रुपया, हर हक' - केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य कूपन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' सभी को प्रयास करना चाहिए: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) हेतु केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज पुडुचेरी में उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी की उपस्थिति में ने इसका उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरूआत भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का एकीकरण पारदर्शिता, दक्षता और लाभार्थियों के सशक्तिकरण को बढ़ाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके हक अधिक स्पष्टता और जवाबदेही के साथ प्राप्त हों। "हर दाना, हर रुपया, हर हक" के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि यह सुधार हकों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा, सुरक्षित और वास्तविक समय के लेनदेन को सक्षम करेगा और कल्याणकारी वितरण तंत्र के भीतर डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक मजबूत करेगा।

श्री जोशी ने बताया कि सीबीडीसी प्रणाली के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल कूपन लाभार्थियों के खातों में प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी (ई₹) के रूप में सीधे जमा किए जाएंगे। लाभार्थी सीबीडीसी कूपन या वाउचर कोड का उपयोग करके उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) या व्यापारी आउटलेट्स से अपनी निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली सुरक्षित, ट्रैक करने योग्य और वास्तविक समय में लेनदेन सुनिश्चित करते हुए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-पीओएस परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करेगी। उन्होंने बताया कि पीएमजीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। यह न केवल गेहूं और चावल बल्कि लाभार्थियों को बाजरा भी प्रदान कर रहा है, जिससे पोषण सुरक्षा मजबूत हो रही है।

श्री जोशी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने यह दर्ज किया है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि केंद्र सरकार के मुफ्त अनाज वितरण और पुडुचेरी केंद्र

शासित प्रदेश द्वारा अतिरिक्त अनाज वितरण के कारण परिवारों के भोजन पर होने वाला खर्च 50 प्रतिशत तक कम हो गया है। मुफ्त अनाज वितरण से प्राप्त बचत का उपयोग लोग दूध, सब्जी आदि जैसी अन्य पौष्टिक वस्तुओं की खरीद के लिए कर रहे हैं। इससे न केवल खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि भारत और विश्व के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त युवा आबादी और कुशल श्रमिकों का सृजन भी होता है। उन्होंने आगे बताया कि इस पायलट परियोजना का जल्द ही 3-4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा और परिणामों के गहन विश्लेषण के बाद सीबीडीसी पहल को आगे बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

श्री जोशी ने यह भी बताया कि लाभार्थियों से उनकी पात्रता के अनुसार अनाज की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए प्रति माह 20 लाख कॉल किए जा रहे हैं। "सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की भावना का अनुसरण करते हुए, श्री जोशी ने देश के सभी नागरिकों से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित देश के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर, पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन ने कहा कि आज का दिन पुडुचेरी के वंचित और मेहनती नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारे परिवारों के लिए गर्व का दिन है और हमारे केंद्र शासित प्रदेश की खाद्य सुरक्षा में एक नया अध्याय लिखने का दिन है। भोजन केवल एक वस्तु नहीं है; यह एक मौलिक मानवाधिकार है। उद्देश्य स्पष्ट है: "इस देश का कोई भी नागरिक भूख से पीड़ित न हो।" केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इन योजनाओं की वास्तविक सफलता अंतिम उपयोगकर्ता तक उनकी निर्बाध पहुंच में निहित है। हमारा लक्ष्य बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और अपात्र लोगों को इससे वंचित रखा जाए। सरकारी सहायता सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली पुडुचेरी में लागू की गई है और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में सीबीडीसी के कार्यान्वयन और नागरिक सशक्तिकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरण में पारदर्शिता के संदर्भ में सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

इस अवसर पर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगासामी ने खाद्यान्न वितरण में बदलाव लाने और पुडुचेरी के नागरिकों को सशक्त बनाने वाली सीबीडीसी की नई पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत अपने लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार द्वारा धन हस्तांतरण और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपनी योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति गरीबों की खाद्य सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा कर रही है और उन्हें भूख से बचा रही है। डीबीटी के माध्यम से बैंक में और अब सीबीडीसी के माध्यम से वॉलेट में आ रही राशि लाभार्थियों के प्रोत्साहन को बढ़ाएगी, उन्हें आत्मविश्वास देगी और उन्हें उपलब्ध धन से अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगी। यह वास्तव में एक महान कदम है जो बिना किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति के मध्यस्थ के सीधे सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से लाभार्थियों को धन उपलब्ध करा रहा है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सीबीडीसी के इस पायलट प्रोजेक्ट और इसके कार्यान्वयन के नेक इरादों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने सीबीडीसी से लाभार्थियों को पात्र धन हस्तांतरण की पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता पर प्रसन्नता व्यक्त की।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) में सीबीडीसी के शुभारंभ के अवसर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत सब्सिडी वितरण हेतु पुडुचेरी में सीबीडीसी की शुरूआत लाभार्थियों तक त्वरित, पारदर्शी और कुशल तरीके से सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह पहल जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) पर आधारित है और डिजिटल सशक्तिकरण को और मजबूत करती है। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को शामिल करने पर विशेष जोर देते हुए इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह प्रणाली लाभार्थियों को एप्लिकेशन के माध्यम से आस-पास के अधिकृत व्यापारी प्रतिष्ठानों का पता लगाने में भी सक्षम बनाती है। उन्होंने बताया कि सीबीडीसी आधारित पीडीएस मॉडल का विस्तार पुडुचेरी में किया जाएगा और बाद में इसे चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में भी लागू किया जाएगा, साथ ही धीरे-धीरे पूरे देश में इसका विस्तार करने की योजना है। उन्होंने सीबीडीसी के पायलट शुभारंभ में आरबीआई, केनरा बैंक और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के प्रयासों और सहयोग की सराहना की।

यह पहल जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्य सब्सिडी के वितरण में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपये को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ढांचे में एकीकृत किया गया है। इस पायलट परियोजना के तहत, खाद्य सब्सिडी चिन्हित लाभार्थियों के सीबीडीसी वॉलेट में प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) टोकन के रूप में सीधे जमा की जाएगी। इन टोकनों का उपयोग केवल अधिकृत व्यापारियों और उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) पर पात्र खाद्यान्न की खरीद के लिए किया जा सकेगा, जिससे सब्सिडी का उद्देश्य-आधारित उपयोग सुनिश्चित होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पिछले कई वर्षों में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र के व्यापक डिजिटल रूपांतरण का कार्य किया है। प्रमुख पहलों में वन नेशन वन राशन कार्ड ढांचे के तहत राशन कार्डों का पूर्णतः डिजिटलीकरण और राष्ट्रव्यापी सुवा'ता, आधार-सक्षम प्रमाणीकरण और वास्तविक समय में लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए ई-पीओएस उपकरणों की तैनाती और राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा-आधारित सत्यापन का कार्यान्वयन शामिल हैं। अन्न चक्र के माध्यम से डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और अन्न सहायता जैसी सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणालियों ने पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को और भी बेहतर बनाया है। सीबीडीसी-आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट परियोजना, पीडीएस संरचना में एक प्रोग्रामेबल संप्रभु डिजिटल भुगतान परत को एकीकृत करके इस सुधार यात्रा का अगला चरण है।

सीमित संख्या में लाभार्थियों के साथ शुरू हुई यह पायलट परियोजना, कल्याणकारी वितरण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण, पारदर्शिता को सुदृढ़ करने और अंतिम छोर तक सेवा वितरण के लिए अधिक कुशल और जवाबदेह शासन ढांचा तैयार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम साबित होने की उम्मीद है।

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन. रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष श्री आर. सेल्वम, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य मंत्री श्री पी.आर.एन. थिरुमुरुगन, पुडुचेरी सरकार के लोक निर्माण मंत्री श्री के. लक्ष्मीनारायण तथा केंद्र सरकार, पुडुचेरी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और केनरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

होम क्रेडिट इंडिया ने पेश किया होली म्यूजिकल कहो इएमआई को हाँ के साथ सुरक्षित वित्तीय विकल्पों का उत्सव

होम क्रेडिट इंडिया ने पेश किया होली म्यूजिकल KahoEMIKoHaan के साथ सुरक्षित वित्तीय विकल्पों का उत्सव

26 फरवरी 2026: अग्रणी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, होम क्रेडिट इंडिया ने आज अपने नए ब्रांड कैंपेन KahoEMIKoHaan की शुरूआत का एलान किया। होली के जीवंत उत्साह और ब्रांड के मूल दर्शन ेल्लर्लिइ पर आधारित यह अभियान, क्रेडिट के प्रति भारतीयों के भावनात्मक जुड़ाव को संकोच और संदेह से बदलकर आत्मविश्वास और स्मार्ट वित्तीय विकल्पों में बदलना चाहता है।

KahoEMIKoHaan के केंद्र में एक सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि निहित है - जहाँ भारतीय बिना किसी संकोच के रंगों के साथ होली का आनंद लेते हैं, वहीं ईएमआई या लोन जैसे वित्तीय निर्णय लेते समय वे अक्सर रुकते हैं और खुद पर संदेह करते हैं। इस म्यूज़िकल कैंपेन के माध्यम से, होम क्रेडिट इंडिया उपभोक्ताओं को क्रेडिट को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले एक 'सार्थक माध्यम' के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें बिना किसी आत्म-ग्लानि या संदेह के प्रगति के लिए 'हाँ' कहने के लिए सशक्त बनाता है।

यह अभियान अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन सहित होम क्रेडिट इंडिया के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव है।

कैंपेन की कथावस्तु

यह कहानी होली के आगमन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें ऐसे दिल को छू लेने वाले बोल हैं जो रुक-रुक कर चलती जिंदगी की लय को दशार्ते हैं—जहाँ सपने अधूरे लगते हैं, जेब थोड़ी खाली महसूस होती है और रोजमर्रा की वित्तीय दिक्कतों के बीच मन के रंग भी फीके पड़ने लगते हैं। इस जीवंत चित्रण के बीच संकोच के वो आम पल दिखाए गए हैं जिनसे हर कोई जुड़ाव महसूस करता है—एक व्यक्ति जो अपने पुराने स्कूटर के साथ संघर्ष कर रहा है, एक युवती जो त्यौहार की रील रिकॉर्ड करते समय फोन खराब होने पर निराश हो जाती है, कॉलेज एडमिशन फॉर्म के पेमेंट पेज पर रुके हुए भाई-बहन, और एक नवविवाहित जोड़ा जो ऑनलाइन पसंद आए डाइनिंग टेबल की कीमत देखकर चुपचाप पीछे हट जाता है।

जैसे-जैसे उनके चारों ओर उत्सव जारी रहता है, उनके मन का संकोच और स्पष्ट होने लगता है। सपने तो जीवित हैं—पर अनिश्चितता उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। उत्सव और इस संयम के बीच एक गहरा अहसास उभरता है: कि जिंदगी रुकती नहीं और आकांक्षाएं कभी धुंधली नहीं पड़तीं—बस झिझक ही रास्ते की बाधा है।

भावनात्मक बदलाव की शुरूआत बहुत छोटी सी होती है। स्क्रीन पर होम क्रेडिट का एक नोटिफिकेशन चमकता है। किसी की नजर टू-व्हीलर शोरूम के बाहर लगे बैनर पर पड़ती है। होम

क्रेडिट ऐप पर कुछ ही टैप्स संदेह को भरोसे में बदल देते हैं। छोटे-छोटे निर्णय अब आत्मविश्वास से भरे विकल्पों का रूप ले लेते हैं।

इसके बाद शुरू होता है रंगों भरा बदलाव—नए फोन से ली गई होली की सेल्फी, नए स्कूटर पर एक खुशनुमा सवारी, एडमिशन मिलने की खुशी मनाते भाई-बहन, और पड़ोसियों के साथ गुजिया बांटते हुए अपना नया डाइनिंग टेबल सजाता एक जोड़ा। इन सभी यात्राओं में, होम क्रेडिट एक शांत लेकिन भरोसेमंद साथी की भूमिका निभाता है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि ईएमआई चुनना अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक समझदारी भरा और जिम्मेदार कदम हो सकता है।

फिल्म का समापन होली के एक सामूहिक उत्सव के साथ होता है, जहाँ सभी पात्र रंगों, खुशी और आत्मविश्वास के एक जीवंत दृश्य में एक साथ आते हैं—जो एक सरल संदेश को रेखांकित करता है: ईएमआई को 'हाँ' कहना, जीवन की प्रगति को 'हाँ' कहना हो सकता है।

कैंपेन पर बात करते हुए, होम क्रेडिट इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आशीष तिवारी ने कहाः "होली स्वतंत्रता, रंगों और एकजुटता का प्रतीक है और इसका जश्न मनाती है; हम यही भावना लोगों के वित्तीय निर्णयों के प्रति नजरिए में भी लाना चाहते थे। डॅङ्गएटक्ङङ्गलंल्ल के साथ, हम ईएमआई और लोन से जुड़ी भावनात्मक हिचकिचाहट को आत्मविश्वास में बदल रहे हैं, और क्रेडिट को एक भरोसेमंद व जिम्मेदार विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा लक्ष्य ग्राहकों को उनकी आकांक्षाओं के लिए 'हाँ' कहने हेतु सशक्त बनाना है—चाहे वह स्मार्टफोन या घरेलू उपकरणों को अपग्रेड करना हो, टू-व्हीलर खरीदना हो, या बड़ी योजनाओं को आकार देना हो। होम क्रेडिट इंडिया में, हम सरल, पारदर्शी, तकनीक-आधारित और सुलभ वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो ग्राहकों

फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश ग्रैंड फिनाले 2026 का भव्य आयोजन

लखनऊ, फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश ग्रैंड फिनाले 2026 का भव्य आयोजन BBD University, लखनऊ में 25 फरवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता में लखनऊ की सानिया मुखर्जी को फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश 2026 का ताज पहनाया गया।

सानिया मुखर्जी का चयन प्रदेश भर से आई 500 से अधिक प्रतिभागियों में से तीन चरणों की ऑडिशन प्रक्रिया के बाद चुनी गई 16 स्टेट फाइनलिस्ट्स में से किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मंच प्रस्तुति के माध्यम से अपनी प्रतिभा

का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

इस भव्य आयोजन की शोभा Nikita Porwal, वर्तमान फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, की गरिमामयी उपस्थिति से और भी बढ़ गई, जिन्होंने कार्यक्रम को विशेष और प्रेरणादायक बना दिया।

इस अवसर पर श्री अमित सैमसन नानू, संस्थापक, कैटवॉक अकादमी, स्टेट लाइसेंसी, फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश, ने बीबीडी ग्रुप के नेतृत्व—श्रीमती अलका दास गुप्ता (माननीय चेयरपर्सन), श्री विराज सागर (माननीय प्रेसिडेंट एवं प्रो-चांसलर, बीबीडी यूनिवर्सिटी), सुश्री सोनांक्षी दास गुप्ता एवं सुश्री देवांशी दास गुप्ता (माननीय वाइस प्रेसिडेंट्स)—के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आयोजन को सशक्त बनाने में उनके सहयोग की सराहना की।

कार्यक्रम को Geetanjali Salon (मेकअप पार्टनर), Gharha Bhandar , Ganpati Collection एवं The vogue Nari (वार्डरोब पार्टनर), Danbro by Mr. Brown (फूड एंड बेवरेज पार्टनर), डिजाइनर Ashfaq Ahmad (ईवनिंग गाउन्स), JD Institute (बैकस्टेज सपोर्ट), A&M Dental Station (स्माइल पार्टनर), ummietummie (गिफ्टिंग पार्टनर) तथा Marshal Security (सिक्योरिटी पार्टनर) का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

सर्वोच्च 3 भारतीय ओ.एम.सी ने पाईन लैब्स को पूरे देश में डिजिटल पेमेंट के आधुनिकीकरण के लिए बहुवर्षीय कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया

लखनऊ, 26 फरवरी 2025: ग्लोबल फिनटेक प्लेटफॉर्म, पाईन लैब्स को भारत में तीन प्रमुख ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों (ओ.एम.सी) द्वारा कई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए गए हैं। ये तीन कंपनियाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल) हैं।

इन तीन ओ.एम.सी से मिले कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, पाईन लैब्स द्वारा भारत में पेट्रोल पंपों और मर्चेंट आउटलेट्स पर डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्रियान्वयन, प्रबंधन और रखरखाव किया जाएगा। इन बहुवर्षीय कॉन्ट्रैक्ट्स का उद्देश्य पॉईंट ऑफ सेल पर पैसे के तीव्र, सुरक्षित और सुगम लेनदेन के लिए पेमेंट रेल को संभालने में पाईन लैब्स की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। इसके अंतर्गत भारत में कुल 130,000 डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाईस तुरंत स्थापित की जाएंगी और संभाली जाएंगी।

आई.ओ.सी.एल के लिए पाईन लैब्स द्वारा उनका लॉयल्टी रिवार्ड्स प्लेटफॉर्म, एक्सट्रापॉवर संभाला जाएगा, जिसका उपयोग भारत में लाखों फ्लीट ऑपरेटर करते हैं। यह प्रोग्राम मजबूत ए.पी.आई इंटीग्रेशन द्वारा निर्मित है, जो फ्यूल मैनेजमेंट, फ्लीट एनालिटिक्स, ट्रिप मैनेजमेंट, सिक्योर चिप और पिन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, जैसे कार्ड, मोबाईल और आरएफआईडी पेमेंट सेवाएं संभव बनाता है।

बी. अमरीश राउ, सी.ई.ओ, पाईन लैब्स लिमिटेड ने कहा, "हम अपने टेक कौशल और भारत में सर्वोच्च ओ.एम.सी के विस्तृत रिटेल फुटप्रिंट्स की मदद से एक टेक-फर्स्ट और मजबूत पेमेंट्स इन्फ्रा एवं विश्वस्तर के प्रीपेड लॉयल्टी रिवार्ड सिस्टम का विकास कर रहे हैं। पाईन लैब्स के सॉफ्टवेयर-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ हम भारत में फ्यूल रिटेल कॉमर्स के तीव्र डिजिटाईजेशन के लिए प्रोडक्ट फीचर ज्यादा तेजी से पेश करेंगे, जिससे ऑन-साईट हस्तक्षेप कम से कम होगा और एक यूनिफाईड रिवार्ड/लॉयल्टी प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा।"

पब्लिक सेक्टर के दिग्गजों के साथ यह फिनटेक पार्टनरशिप आसान, सुरक्षित और सुगम डिजिटल पेमेंट्स एवं लॉयल्टी रिवार्ड अनुभवों के माध्यम से प्रमुख भारतीय ओ.एम.सी और पाईन लैब्स द्वारा ग्राहकों पर केंद्रित प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है।

अमृता की आजाद रूह को कथक के घुंघरू देंगे आवाज, लखनऊ में सजेगी साहित्य और कला की महफिल

लखनऊ। मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, कहने वाली कलम की मलिका अमृता प्रीतम एक बार फिर लखनऊ की सरजमीं पर जिंदा होंगी। आगामी 28 फरवरी को संत गाडगे प्रेक्षागृह में कल्चरल क्वेस्ट की ओर से नृत्य नाटिका आजाद रूह का मंचन किया जा रहा है।

यह मात्र एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सफर है, विभाजन के उस गहरे दर्द से लेकर अमृता और इमरोज की उस खामोश मोहब्बत तक, जिसने दुनिया को प्यार के नए मायने सिखाए। कथक गुरु सुरभि सिंह के निर्देशन और संगीत में पिरोई गई यह नाटिका नारी के संघर्ष, साम्प्रदायिकता की आग और एक आजाद रूह की

बेबाकी को मंच पर जीवंत करेगी।

शाम का आकर्षण सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं है। इस मौके पर संजय मल्होत्रा हमनवा की बहुप्रतीक्षित पुस्तक अमृत इमरोज का विमोचन भी होगा। साथ ही, साहित्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली 11 हस्तियों को अमृता प्रीतम सम्मान से नवाजा जाएगा। सम्मानित होने वालों में पद्मश्री विद्या विन्दु सिंह और हिमांशु वाजपेई जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं।

यह कार्यक्रम उन तमाम रूहों को समर्पित है जो सरहदों और रूढ़ियों से परे होकर जीना जानती हैं।

कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास मंत्री, दया शंकर सिंह, परिवहन मंत्री और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल उपस्थित रहेंगी। तारीख याद रखिएगा 28 फरवरी, शाम 6:30 बजे। आइए, उस रूह को महसूस करें जिसने कभी झुकना नहीं सीखा।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

परिवर्तन चौक पर पुलिस की छात्रों से नोकझोंक:बोले- लखनऊ विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बना, डीएम ऑफिस कूच किया

लखनऊ, (जीएनएस)। लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित लाल बारादरी सील किए जाने के विरोध में बापसा, भाकपा माले और आइसा के छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर रोक होने के कारण परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए।

डीएम ऑफिस जाने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर ही पहुंचकर उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अड्डा बना दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद लाल बारादरी सील किया गया है।

इसके पहले 25 फरवरी की रात तौकील गाजी ने इस संबंध में एक वीडियासे जारी किया था। उसमें कहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन तक धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रॉक्टर ने बातचीत करके 2 दिनों का समय मांगा था, लेकिन वह बीत गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ताला खोलने को लेकर कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। न ही दोबारा कोई बातचीत की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 फरवरी को नोटिस जारी करके परिसर में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दिया है।

वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देना चाहती केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी - चेतन शर्मा

अभिनव भारत पार्टी के अधिवेशन में जुटे देश के साधु-संत

लखनऊ। क्रान्तिकारी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज यहां इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुये अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करते हुये कहा है कि केन्द्र सरकार वीर सावरकर को भारत-रत्न देने के लिये गंभीर नहीं है। अधिवेशन में पार्टी के सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि वीर सावरकर ने अपने युवावस्था में ही अभिनव भारत संगठन की स्थापना कर पराधीन भारत में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्जवलित की थी, उन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वप्न नहीं देखा बल्कि उसके लिये कालकोठरी में अमानवीय यातनायें सही। अंडमान की सेल्युलर जेल की दीवारें आज भी उस तप, त्याग और तेज की साक्षी है, ऐसे व्यक्तित्व को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वीर सावरकर को भारत रत्न दिये जाने को लेकर कह चुके है

कि सावरकर के योगदान को देखते हुये यदि उन्हें भारत-रत्न मिलता है तो इससे भारत-रत्न का सम्मान होगा। श्री शर्मा ने बताया कि अभिनव पार्टी ने पिछले वर्ष वीर सावरकर को भारत-रत्न दिलाने की मांग को लेकर देशभर में सावरकर सम्मान यात्रा निकालकर देश की राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित आठ सौ ज्ञापन देश के विभिन्न हिस्सों से दिये गये, लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई विचार नहीं कर रही है, इसके लिये पार्टी निरन्तर संघर्ष करती रहेगी।

श्री शर्मा ने अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को लेकर कहा कि देश में गाय की सुरक्षा के लिये माता का दर्जा देने के साथ-साथ उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाये, तभी जाकर देश में गाय माता को बचाया जा सकता है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा केवल भावनात्मक निर्णय नहीं होगा बल्कि यह एक ठोस कानूनी संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चेतन शर्मा ने कहा कि अभिनव भारत पार्टी राज्य के चुनावी रणभूमि में उतरने के लिये पूरी तरह तैयार है, और लगभग तीन सौ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। चुनावी रणनीति को लेकर अभिनव भारत पार्टी जल्द ही अन्तिम रूप देकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर जायेगी।

इससे पहले इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में अधिवेशन का शुभारम्भ भारत माता की स्तुति और वन्देभारत गीत के साथ दीप प्रज्जवलित कर हुआ। इस मौके पर प्रमुख रूप से मालेगांव मामले में बरी हुये मेजर रमेश उपाध्याय, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कम्प्यूटर बाबा, पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री ममता झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. नीलेन्द्र गौतम, श्रीमती चित्रा दलाल, स्वरूपानंद महाराज के शिष्य त्रिभुवन दास, कार्तिक गिरी, सर्वेश मिश्रा, महामण्डलेश्वर अमरेशानन्द गिरी सहित देशभर से आये पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।

बीमार बच्ची के इलाज के लिए ससुराल पहुंची महिला से मारपीट का आरोप

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के शाहनगर गांव की निवासी फरजाना बेगम ने अपने ससुरालीजनों पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला का कहना है कि वह अपनी बीमार एक वर्षीय बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने ससुराल गई थी, जहां उसके साथ मारपीट की गई।

पुलिस को दी गई तहरीर में फरजाना बेगम ने बताया कि उसका पति मेहताब खाड़ी देश में रहकर नौकरी करता है। आरोप है कि कुछ समय पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे उसके तीन बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वह अपने मायके में रहकर मेहनत-मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण कर रही है।

महिला के अनुसार हाल ही में उसकी एक वर्ष की मासूम बच्ची गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज कराया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उपचार में दिक्कत आने लगी। मजबूर होकर वह 24 फरवरी को अपने ससुराल मदद मांगने पहुंची।

आरोप है कि वहां देवर इमरान उर्फ नन्नू, जेठ अल्ताफ तथा ननद साजिया ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की। महिला का कहना है कि सहायता करने के बजाय उसे अपमानित किया गया और धमकी दी गई कि उसका पति विदेश में बैठा है, वह उसे छोड़ देगा।

घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ इलाज के दौरान तोड़ा दम

(जीएनएस)।

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के नाज भट्ठा स्थित कोल्ड स्टोर के पास बुधवार की रात को शादी समारोह में शामिल होने जा रहे दो बाइकों की आमने-सामने की भिंड़त में तीन लोगों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसमें एक की गुरुवार को सुबह अस्पताल मौत हो गई।

थाना क्षेत्र के तौरा गांव निवासी नरेश पासवान के पुत्र कंधई की बुधवार को शादी थी। बरात में शामिल होने नरेश के साले मोतीलाल पासवान (40) निवासी मोहम्मदपुर गौंती अपने पुत्र धर्मेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से तथा समधी कमलेश कुमार पासवान (60) निवासी भैरवां कला साइकिल से शाम को गांव पहुंचे। दोनों लोग गांव के ही पड़ोसी दुर्गेश पासवान (23) की मोटरसाइकिल में बैठकर शाहपुर के पास रसूलपुर गांव बरात के लिए निकले। वहीं दूसरी ओर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई पतारा गांव निवासी रामू (33) अपने भतीजे अरविंद (23) के साथ बाइक से खागा कोतवाली के कल्लनपुर गांव निमंत्रण में जा रहे थे। दोनों बाइकों की कोल्ड स्टोर के पास भिड़ंत हो गई। जिससे पांचों लोग घायल हो गए। पुलिस इन्हें हथगाम ले गई। यहां चिकित्सक ने अरविंद, दुर्गेश और कमलेश को मृत घोषित कर दिया था और गंभीर रूप से घायल रामू और

मोतीलाल को सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। इसमें मोतीलाल पासवान की भी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मोतीलाल मजदूरी का कार्य करते थे। परिवार में पत्नी आशा, पुत्र राजेन्द्र कुमार, घनश्याम कुमार, धर्मेंद्र कुमार पुत्री सविता देवी हैं। कमलेश कुमार भी मजदूरी का कार्य करते थे। परिवार में पत्नी मैकी देवी, पुत्र रंजीत कुमार, श्रवण कुमार, सचिन, शिवा, पुत्री गुड़िया, माया, सीमा, सरिता, कमला हैं। मृतक दुर्गेश कमाने के वास्ते बाहर रहता है। परिवार में मां केशपती, भाई सियम्बर, बृजेश और बहन सोना हैं। 1 माह पहले दुर्गेश मुम्बई से कमाकर घर आया था। उसकी करीब 4 माह पहले गड़रियन का पुरवा गांव में सगाई तय हो गई और बयाना हो गया था और शादी की तारीख रखना बांकी था।

डॉ. आनंद प्रकाश मिश्र, वो डॉक्टर, जिसने मंच को बनाया समाज सुधार का नश्तर

आमतौर पर एक डॉक्टर का काम अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित रहता है, लेकिन शाहजहाँपुर के डॉ. आनंद प्रकाश मिश्र ने इस धारणा को बदल दिया। 1957 में हरदोई के ग्राम घसा में जन्मे डॉ. मिश्र ने महसूस किया कि शरीर के रोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक समाज में फैली कुरीतियाँ और अज्ञानता है। बस, यहीं से शुरू हुआ चिकित्सा सेवा से समाज सेवा तक का एक अनूठा सफर।

डॉ. मिश्र ने केवल दवाइयाँ नहीं दीं, बल्कि कलम उठाकर नाटक लिखे और खुद मंच पर उतरकर समाज को आईना दिखाया। उनकी पत्नी नलनी मिश्रा ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया और नाटकों में मुख्य भूमिकाएँ

निभाकर इस मिशन को नई ताकत दी। उनकी संस्था 'सजन समाज सेवा समिति' ने देश के कोने-कोने में चेतना जगाई।

डॉ. मिश्र के नाटकों ने समाज के हर दुखते नस पर प्रहार किया, नशा मुक्ति पतन स्मैक/गुटखा के खिलाफ और फैसला, बिदा टीबी पर और एक ही भूल पोलियो पर भागीरथी और गंगा मैया भला करें, कन्या भ्रूण हत्या, स्वच्छता, नारी सशक्तिकरण और जनसंख्या विस्फोट।

उनकी कला और जुनून का जादू ऐसा था कि शक्ति कपूर, सुदेश बेरी और अली खान जैसे बॉलीवुड कलाकार भी शाहजहाँपुर खिंचे चले आए। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए उन्हें 'जनपद रत्न' जैसे कई सम्मान मिले। चर्चा है कि उनके समर्पण के कारण अब उन्हें सेंसर बोर्ड की सदस्यता और जल संरक्षण के लिए जल पुरुष सम्मान से भी नवाजा जा सकता है।

डॉ. आनंद प्रकाश मिश्र ने यह साबित कर दिया कि हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं होते। जब एक पेशेवर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को सामाजिक मिशन बना लेता है, तो वह केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच का उपचार करता है। उनका पूरा परिवार जिसमें डॉक्टर और विशेषज्ञ शामिल हैं, आज समाज के लिए एक मिसाल है।

अवैध कब्जे का आरोप, जिलाधिकारी से की गई कार्रवाई की मांग

(जीएनएस)।

कौशाम्बी

चायल तहसील क्षेत्र के ग्राम पेरई तिलहापुर मोड़ में स्थित श्री सीताराम स्थानीय संत सेवा समिति एवं ट्रस्ट की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है संगठन के महामंत्री महेश्वरदास ने जिलाधिकारी को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि ट्रस्ट की जमीन, गाटा संख्या 218 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुरक्षित है, जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अस्वीकार्य है महामंत्री ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जा तत्काल हटवाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी स्थानीय लोगों में भी इस प्रकरण को लेकर चर्चा है और वे प्रशासन से निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं

लखनऊ के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. पी. सी. गुप्ता को भारतीय डिजाइन पेटेंट प्राप्त

लखनऊ।

लखनऊ स्थित प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश डॉ. पी. सी. गुप्ता को AI based Device for business strategy planning and risk forecasting' शीर्षक से विकसित नवाचार हेतु भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह पंजीकरण डिजाइन अधिनियम, 2000 एवं डिजाइन नियम, 2001 के अंतर्गत प्रदान किया गया है ` यह अभिनव डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरण से संबंधित है, जो व्यवसायिक रणनीति निर्माण एवं जोखिम पूवार्नुमान में सहायक है। यह उपकरण आधुनिक आर्थिक विश्लेषण, डेटा आधारित निर्णय-निर्माण तथा संस्थागत प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उपलब्धि में डॉ. पी. सी. गुप्ता के साथ अन्य सह-आविष्कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें डॉ. महेन्द्र कुमार नामदेव, डॉ. मुस्ताक आलम, पूजा उपाध्याय, डॉ. किरण सचदेवा, डॉ. श्वेता सिंह, सुमोना घोष,

विशाल मिश्रा, अवधेश यादव एवं अपराजिता श्रीवास्तव शामिल हैं। डॉ. पी. सी. गुप्ता, जो कि लखनऊ के एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं अर्थशास्त्री हैं, एवं डॉ. मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ अर्थशात्री द्वारा भी अपनी अर्थशास्त्र पर पुस्तकों हेतु सराहना पत्र एवं मार्गदर्शन पा चुके है ने इस उपलब्धि को शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के समन्वय का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन भविष्य में उद्योग, शिक्षा एवं नीति-निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाएगा। शैक्षणिक एवं बौद्धिक जगत में इस उपलब्धि को अत्यंत गौरवपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल संस्थान बल्कि लखनऊ शहर एवं प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है।

मूरतगंज ब्लॉक के पक्सराई गांव में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण में बड़ा घोटाला, मानकों की अनदेखी

कौशाम्बी

मूरतगंज विकास खंड अंतर्गत पक्सराई गांव में बन रहे सरकारी अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं निर्माण में मानक के विपरीत रद्दी किस्म की बालू और घटिया ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की घोर लापरवाही के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है जो कानूनन अपराध है पढ़ाई-लिखाई की उम्र में बच्चों को मजदूरी में झोंककर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग आंख मूंदे बैठे हैं

इतना ही नहीं, अन्त्येष्टि स्थल के ठीक बगल स्थित सरकारी तालाब की खुदाई मानकों से कहीं अधिक कराई गई है।

सूत्र JCB मशीन लगवाकर जरूरत से ज्यादा खुदाई कराई गई और निकाली गई मिट्टी को ग्राम प्रधान द्वारा बेच दिया गया इससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ तालाब के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है

जिला मजिस्ट्रेट ने 04 मार्च को आबकारी की समस्त दुकानों के बन्द रखने के दिए आदेश

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त देशी शराब/कम्पोजिट मदिरा/भॉग/एफ. एल.-16/17, एफल.एल.-2, 2बी. एवं सी.एल.-2 आदि मादक पदार्थो के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को होली (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण) दिनांक 04 मार्च,2026 को बन्द रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

जिला मजिस्ट्रेट ने 04 मार्च को आबकारी की समस्त दुकानों के बन्द रखने के दिए आदेश

कौशाम्बी। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त देशी शराब/कम्पोजिट मदिरा/भॉग/एफ. एल.-16/17, एफल.एल.-2, 2बी. एवं सी.एल.-2 आदि मादक पदार्थो

के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को होली (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण) दिनांक 04 मार्च,2026 को बन्द रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

ग्लोबल एग्रोटेक 2026 के पहले दिन बी.एल. एग्रो ने प्रस्तुत की अपनी विविध क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला

लखनऊ में 3 दिवसीय प्रदर्शनी-संगोष्ठी का उद्घाटन कृषि मंत्री ने किया

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, श्री ब्रजेश पाठक ने बीएल एग्रो के स्टॉल का उद्घाटन किया।

लखनऊ, 26 फरवरी: भारत के अग्रणी एग्रो-उत्पाद ब्रांड बी.एल. एग्रो ने गुरुवार को लखनऊ स्थित करफ्क -भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (करफ्क) में शुरू हुए 'ग्लोबल एग्रोटेक 2026' प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के पहले दिन अपनी विविध क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया।तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन श्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एकीकृत मंच पर वरिष्ठ नीति-निमार्ताओं, अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत के नेताओं और प्रगतिशील किसानों की सहभागिता रही। उद्घाटन समारोह में दिनेश प्रताप सिंह, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान, कृषि विपणन एवं निर्यात तथा रविंदर, आईएएस, प्रमुख सचिव, कृषि भी उपस्थित रहे।

श्री पाठक ने बीएल एग्रो ग्रुप के पवेलियन का उद्घाटन किया और उन्हें कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, एकीकृत वैल्यू चेन, डेयरी विकास, वैज्ञानिक जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म तथा क्लाइमेट-टेक आधारित जोखिम बुद्धिमत्ता ढाँचों सहित समूह के सक्रिय योगदानों के बारे में जानकारी दी गई। बीएल एग्रो की सहायक कंपनियों— लीड्स कनेक्ट, लीड्स जेनेटिक्स और लीड्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स —ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो कृषि की एकीकृत वैल्यू चेन में समूह की बढ़ती प्रमुखता को दशार्ता है।

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर श्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश कृषि उन्नति और खाद्य प्रसंस्करण उत्कृष्टता का एक तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। बीएल एग्रो जैसी कंपनियों की इस तरह के मंचों पर भागीदारी उत्तर प्रदेश की एग्री-इनोवेशन, वैल्यू एडिशन और किसान सशक्तिकरण में बढ़ती ताकत को दशार्ती है। ऐसे प्रयास तकनीक, उद्यम और ग्रामीण विकास के बीच सेतु को मजबूत करते हैं। मैं राज्य की कृषि प्रगति में निरंतर योगदान के लिए बीएल एग्रो को शुभकामनाएं देता हूँ।'

उद्घाटन अवसर पर माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यानिकी, कृषि विपणन एवं निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 'यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम भारतीय कृषि के अगले विकास चरण पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय कृषि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। सतत कृषि के लिए सफल पीपीपी मॉडल ही आगे का मार्ग है। ऐसे आयोजन सभी हितधारकों को एक साथ लाकर स्थायी भविष्य की दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं।'

कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए घनश्याम खंडेलवाल, चेयरमैन, बी.एल. एग्रो एवं कउत्र्क्ष वढरअउ ने कहा 'तीन दिवसीय ग्लोबल एग्रोटेक देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह क्षेत्र भारतीय ऋद्ध में सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक है और आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग वर्तमान में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसलिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जिम्मेदारी हम पर है। आज हमने उत्तर प्रदेश की कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने, डेयरी के आधुनिकीकरण में तेजी लाने, एग्री-फाइनेंस की पहुंच बढ़ाने और प्रौद्योगिकी-सक्षम कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। ग्लोबल एग्रोटेक 2026 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने के लिए एक एकीकृत और बुद्धिमत्ता-आधारित कृषि व्यवस्था के निर्माण की दिशा में हमारा प्रयास है—जहां नीति दृष्टि, वैज्ञानिक प्रगति और निजी क्षेत्र का क्रियान्वयन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।'

उद्घाटन दिवस पर 'उत्तर प्रदेश कृषि विकास बैठक' का आयोजन होटल रेडिसन, लखनऊ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बी.एल. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं कउत्र्क्ष वढरअउ चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल ने की। इस बैठक में श्री मुकेश कुमार मेश्राम (आईएएस), अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन, तथा श्री रविंदर(आईएएस) प्रमुख सचिव, कृषि भी उपस्थित रहे। साथ कोट डी'आइवोर, क्यूबा, स्पेन और ब्राजील के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।डेवलपमेंट मीट में पशुधन और डेयरी क्षेत्र के रूपांतरण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर ब्राजील की अग्रणी डेयरी जेनेटिक्स एवं फार्म मैनेजमेंट कंपनी 'फजेंडा फ्लोरेस्टा' के संस्थापक रोजेरियो बारोस एवं रोबर्टा बर्टिन बारोस भी मौजूद थे। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने और स्वदेशी नस्लों को सुदृढ़ करने में वैज्ञानिक प्रजनन, जीनोमिक्स तथा प्रजनन तकनीकों की भूमिका को रेखांकित किया।

इजराइल में भारतीय यूपीआई चलेगा, मोदी-नेतन्याहू की बैठक में समझौता: मोदी

बोले- जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इजराइल आना मेरे लिए गर्व की बात

(जीएनएस)।

पीएम मोदी और नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन हैं। मोदी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले यरूशलम के होलोकॉस्ट मेमोरियल 'याद वाशेम' पहुंचे। यहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं, पीएम मोदी ने इजराइली राष्ट्रपति को

भारत आने का न्योता दिया। फिर पीएम मोदी और इजराइली पीएम नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया है कि इजराइल में भी अब भारत का वढकपेमेंट सिस्टम चलेगा। PM मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करेगा।

मोदी बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट को भी संबोधित किया। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

लखनऊ में इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की मूर्ति स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा भव्य रूप से संपन्न

लखनऊ, 26 फरवरी 2026। राजधानी लखनऊ के चौपटिया क्षेत्र स्थित फाटक जियालाल (गेट के अंदर पुराने पीपल के पास) में नवनिर्मित इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरुवार को इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा का भव्य एवं दिव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करती हुई पुनः मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बनाते रहे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई। इसके उपरांत वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि-विधान के साथ इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। साथ ही इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान जी के साथ मां भगवती दुर्गा जी तथा भव्य शिवलिंग के साथ शिव परिवार की स्थापना भी विधि-विधानपूर्वक की गई। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर पूर्णतः भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के पार्षद मनीष रस्तोगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान जी की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के संकटों का नाश होता है। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण क्षेत्रवासियों के सहयोग और सामूहिक प्रयास से संभव हुआ है, जो सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। सायं 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके उपरांत सायं 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के माध्यम से प्रभु का गुणगान किया और वातावरण को पूर्णतः आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने क्षेत्र में सुख-शांति, समृद्धि और सद्भाव की कामना की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र सिद्ध होगा।

अनपरा तापीय परियोजना के सीजीएम बने इं अजय कटियार

अधिकारियों तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंटकर नवागत सीजीएम का किया स्वागत

सीजीएम को पूर्ण सहयोग का दिया भरोसा

बिजली कार्मिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से किया जायेगा निस्तारण - सीजीएम अजय कटियार

नवनियुक्त सीजीएम का स्वागत व निवर्तमान सीजीएम का विदाई समारोह किया गया

-- आर पी सिंह

अनपरा (सोनभद्र)। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी आदेश के तहत अनपरा तापीय परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक इं जेपी कटियार को मुख्य महाप्रबंधक तापीय परिचालन इकाई लखनऊ तथा जवाहरपुर तापीय परियोजना के परियोजना प्रमुख इं अजय कटियार को मुख महाप्रबंधक अनपरा तापीय परियोजना की नई जिम्मेदारी मिलने पर गुरुवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत सीजीएम अनपरा इं अजय कटियार को परियोजना के अधिकारियों तथा

विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया तथा बधाई दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कार्मिकों को आशा है कि नए सीजीएम भी परियोजना की समस्यायों को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों समेत सभी वर्ग के हित के लिए कार्य करेंगे।

वही इस उपलक्ष में अनपरा तापीय परियोजना के अधिकारियों द्वारा कॉलोनी परिसर स्थित प्रेक्षागृह में इं जेपी कटियार के विदाई एवं इं अजय कटियार के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।इस अवसर पर अभियंताओं ने दोनों मुख्य मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा पूर्ववर्ती यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा बिजली विभाग के विघटन के पश्चात राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विभिन्न परियोजनाओं पर उनके तकनीकी दक्षता,कठिन परिश्रम, सहयोगी भावना,निर्णय लेने की क्षमता तथा कुशल मैनेजमेंट से उनके द्वारा हासिल किए गए प्लांट की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनो अभियंताओं को नई जिम्मेदारी मिलने से अभियंताओं को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि कम लागत में अधिक से अधिक सतत विद्युत उत्पादन होगा, स्थानीय समस्याओं का प्रमुखता से निस्तारण होगा तथा इनके कुशल मार्गदर्शन में परियोजना नई - नई कीर्तिमान स्थापित करेगा। इं जेपी कटियार द्वारा अनपरा तापीय परियोजना को नई ऊंचाईयों पर ले जाने में बहुमूल्य योगदान तथा कार्मिक हितों को देखते हुए कॉलोनी परिसर में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई तथा अधिकारियों द्वारा स्मृति भेंट कर उन्हे भावभीनी विदाई दी गई।

इस अवसर पर महाप्रबंधक अ एवं ब इं दूधनाथ,महाप्रबंधक सिविल इं राजीव कुमार, महाप्रबंधक द इं प्रशांत त्रिपाठी,सीएमओ डॉ अमरनाथ बरनवाल, अधीक्षण अभियंता मुख्यालय इं कमेंद्र सिंह, इं उत्पल शंकर, इं अच्युतेश कुमार, इं एसके रजक, इं आलोक त्रिपाठी,इं चंद्र प्रकाश, इं वीके सिंह, इं आरके सिंह, इं वीके दिनकर, इं महेंद्र सिंह,अधिशासी अभियंता इं पवन तिवारी, इं राम ज्ञान सिंह,इं अदालत सिंह, इं मनोज यादव, इं सुभाष पटेल, इं राम प्यारे वर्मा, इं प्रमेंद्र चौधरी, इं बीआर पटेल, इं राजेश पांडेय, इं अभय कुमार, अभिषेक सिंह, वीके आनंद, मुकेश जायसवाल, श्याम बिहारी सिंह, बृज बिहारी यादव, राज कुमार यादव,राज कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह,सीलियम मसीह, जितेंद्र जायसवाल, इंद्रेश सिंह, सूरज गुप्ता, फिरोज अंसारी, वीरेंद्र वर्मा, विकाश कनौजिया, सुधीर पटेल, एस के मधुकर, प्रभाकर सिंह, अखिलेश कुमार, नीरज जायसवाल, योगेंद्र मिश्रा, महबूब अहमद, इंद्र कुमार सिंह, राकेश जायसवाल, प्रमोद मिश्रा, कैलाश नाथ पाल, सुरजन सिंह, मंगल मणि,राम जन्म, अभय सिंह, समेत तमाम अधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एवं भारत के स्थायी मिशन ने जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन में विशेष व्यापार सुविधा सत्रों का आयोजन किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में व्यापार सुविधा समिति की बैठक के दौरान 24 फरवरी 2026 को जिनेवा में व्यापार पर विशेष सत्रों का आयोजन किया।

विशेष सचिव और सदस्य (सीमा शुल्क), श्री सुरजीत भुजबल ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सीबीआईसी सत्रों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में व्यापार सुगमता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित दो सत्र आयोजित किए गए, जिनमें डब्ल्यूटीओ व्यापार सुगमता समझौते (टीएफए) के तहत भारत द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यक्रम जुलाई 2026 में होने वाली भारत की आठवीं व्यापार नीति समीक्षा से पहले आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों और सचिवालय के प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी में लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और यह भारत के अनुभव और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुविधा अधिनियम (टीएफएपी) प्रतिबद्धताओं का अनुपालन हासिल करने के बाद, भारत राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी 3.0) के अंतर्गत "टीएफए प्लस" उपायों की ओर बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होना है। व्यापार सुविधा पर सत्र के दौरान, भारतीय सीमा शुल्क प्रतिनिधिमंडल ने

सीमा शुल्क सुधारों में अपने 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' और व्यापक डिजिटलीकरण और प्रक्रिया पुनर्गठन के माध्यम से एक सरल, संपर्क रहित और कागज रहित सीमा शुल्क प्रणाली बनाने के अपने अग्रणी प्रयासों की जानकारी दी।

भारत ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने सभी टीएफए प्रतिबद्धताओं को 100 प्रतिशत अधिसूचित कर दिया है। यह प्रगति भारत की निम्नलिखित के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है:

पारदर्शिता बढ़ाना

विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना, और

सीमा पार व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना

सीबीआईसी ने अपने उन्नत और स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों का प्रदर्शन निम्नलिखित रूप में किया:

सिंगल विंडो इंटरफेस के साथ व्यापक सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली

एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

अधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) कार्यक्रम

आगमन से पहले सीमा शुल्क प्रक्रिया और मूल डेटा का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान (ईओडीईएस)

इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस)

आधुनिक सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क, और

समन्वित सीमा प्रबंधन (सीबीएम) और आभासी व्यापार गलियारों (वीटीसी) पर पहल

क्षमता निर्माण सत्र में विकासशील और अल्पविकसित देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने में भारत की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के माध्यम से भारत, भारतीय और विदेशी सीमा शुल्क प्रशासन के अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारत की केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। इन दोनों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्रमशः एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह बताया गया कि वर्ष 2022 से, एनएसीआईएन ने 65 प्रशिक्षण आयोजित किए हैं और लगभग 30 देशों के 1,800 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को इन पहलों से लाभ हुआ है। इनमें से कई प्रशिक्षण डब्ल्यूसीओ, एडीबी और अन्य जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आयोजित किए गए थे। इसी प्रकार, सीआरसीएल ने 300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। भारत ने व्यापार सुविधा समझौते की प्रतिबद्धताओं को लागू करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की। प्रतिभागियों ने इन संस्थानों के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और भारत के प्रमुख संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की सराहना की।

विशेष सचिव और सदस्य (सीमा शुल्क), श्री सुरजीत भुजबल ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत द्वारा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण ने व्यापार वृद्धि और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सीमा शुल्क का डिजिटल इकोसिस्टम व्यापारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, बैंकों और रसद संचालकों को जोड़ता है, सीमा शुल्क दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को सुगम बनाता है, जिससे लेनदेन लागत कम होती है और निकासी का समय कम होता है।

रस्तोगी स्वास्थ्य केन्द्र में 57 लोगों ने किया रक्तदान, बने प्रेरणा स्रोत

-अब हर तिमाही लगेगा रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों को मिलेगा ब्लडः हरी जीवन

-केजीएमयू की टीम ने कराया रक्तदान

लखनऊ। खालाबाजार स्थित रस्तोगी स्वास्थ्य केन्द्र पर लखनऊ हरिश्चन्द्र वंशीय समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इसमें कुल 57 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान कराने के लिए केजीएमयू की टीम पहुंची, कुल 75 लोगों ने पंजीकरण कराया था लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते 18 लोग अनफिट हो गये। समाज के संरक्षक

हरी जीवन रस्तोगी ने बताया कि पहली बार आयोजित यह रक्तदान शिविर आशा से बढ़कर सफल साबित हुआ है। अब हर तिमाही रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। डोनर कार्ड से जरूरतमंदों की मदद की जाएगी।

शिविर का उद्घाटन केजीएमयू के रेस्पिरेटिरी विभागाध्यक्ष डा. सूयार्कांत एवं अखिल भारतीय हरिश्चन्द्र वंशीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रस्तोगी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डा. सूयार्कांत ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि या कमजोरी नहीं आती है, इसकी प्रतिपूर्ति एक सप्ताह में हो जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रस्तोगी ने कहा कि लखनऊ हरिश्चन्द्र वंशीय समाज ने अनेक उल्लेखनीय कार्य कर पदचिह्न बनाए हैं। अब इसी क्रम में रक्तदान जैसे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज हित में सबसे बड़े पुण्य का कार्य है। समाज के हर वर्ग के लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान में खासतौर पर डॉक्टर मनोज रस्तोगी (65 वर्ष) ने 85 वीं बार रक्तदान करके लोगों ने लिए प्रेरणास्रोत बने हैं। शिविर के संचालन में उपाध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, महामंत्री प्रदीप रस्तोगी, हरिश्चन्द्र दर्पण समिति के अध्यक्ष गिरीश रस्तोगी, स्टार्टअप समिति के अध्यक्ष सुधांशु, मंत्री आशुतोष, सुहासिनी की उपाध्यक्ष सीमा रस्तोगी ने सहयोग किया।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान

निफ्टम-कुंडली में अन्वेष-2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उद्घाटन

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टम-कुंडली) में उभरते और बेहतर स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के लिए उन्नत अगली पीढ़ी की परिकल्पना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (अन्वेष-2026) का आज उद्घाटन किया गया। तीन दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, उद्योग प्रतिनिधि, निर्यातक, उद्यमी और नीति निमार्ता भाग ले रहे हैं।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक अरब 40 करोड़ लोगों के देश के लिए प्रौद्योगिकी आधारित विकास अत्यावश्यक है। गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के लिए नवाचारों, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों तक पहुंचाना होगा।

श्री पासवान ने उपभोक्ता

जीवनशैली में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए रेडी-टू-ईट (आरटीई) और रेडी-टू-कुक उत्पादों की बढ़ती मांग का जिक्र किया, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार के लिए अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि भारत में उत्पादन की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद, मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उन्होंने याद दिलाया कि 11 वर्ष पूर्व, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और भारत को वैश्विक खाद्य भंडार के रूप में स्थापित करने के लिए, भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार, जिसमें ई-कॉमर्स भी शामिल है, में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने कहा कि लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भारतीय खाद्य उत्पाद विश्व भर के हर भोजनालय में मौजूद हों। यदि भारतीय मानकों को वैश्विक मान्यता प्राप्त करनी है तो गुणवत्ता और नियामक मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने किसानों के हितों की रक्षा करते हुए 23 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में फैली गलत धारणाओं को दूर करने का आ'न किया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने इस अवसर पर कहा कि 'अन्वेष' का अर्थ है "अन्वेषण और अधिग्रहण"। उन्होंने निफ्टम को सतत विकास और स्वस्थ खाद्य प्रणालियों का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) 14 योजनाओं में से एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली योजना है।

श्री जोशी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 10,900 करोड़ रुपये के आवंटन में से अब तक 2,625.04 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जो कुल आवंटन का लगभग 24 प्रतिशत है। योजना के तहत 2.5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुकाबले 3.29 लाख रोजगार पहले ही सृजित किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 131 प्रतिशत है और योजना की महत्वपूर्ण सफलता को दर्शाता है।

विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता शकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड ने खाद्य प्रसंस्करण में कार्रवाई-उन्मुख और समाधान-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के पूर्व अध्यक्ष टीजी सीताराम ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है, जो एक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप है।

निफ्टम-कुंडली के निदेशक हरिंदर सिंह ओबेरॉय ने इस बात का उल्लेख किया कि अन्वेष-2026 ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और साझा शिक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने के लिए भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग आवश्यक है।

इससे पहले, श्री पासवान ने अन्वेष-2026 प्रदर्शनी का दौरा किया और इस आयोजन में प्रदर्शित नई प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और उत्पादों की समीक्षा की।

इस सम्मेलन में 1,000 से अधिक

कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 का शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने डीएचआर ने मेडिकल कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 का शुभारंभ किया; डीएचआर को 4,800 करोड़ रुपये का आवंटन जैव चिकित्सा अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित 100 से अधिक बहुविषयक अनुसंधान इकाइयों को एक साथ लाता है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाले जैव चिकित्सा अनुसंधान रिसर्च कनेक्ट 2026 पर ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की है।

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के मेडिकल कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 का शुभारंभ किया। 26-27 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाला यह दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन देशभर के 100 से

अधिक मेडिकल कॉलेजों को एक मंच प्रदान करेगा। यहां देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु केंद्रीय योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अनुसंधान इकाइयां (एमआरयू) स्थापित की गई हैं ।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अध्यक्ष डॉ. अभिजात चंद्रकांत शेठ भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों की सराहना की और संकाय सदस्यों से चिकित्सा अनुसंधान के स्तर को ऊंचा उठाने का आग्रह किया ताकि देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके।

26 और 27 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिनिधि अपनी गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और बेहतर अनुदान प्रस्ताव लेखन, प्रशिक्षण अवसरों और जैव चिकित्सा अनुसंधान के तकनीकी पहलुओं से संबंधित विषयों पर संवादात्मक व्याख्यानों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में शामिल हो रहे है। इन प्रयासों का उद्देश्य आपसी अनुभवों से सीखना और अपने संस्थानों के शोधकताओं की उच्च गुणवत्ता वाले जैव चिकित्सा अनुसंधान करने की क्षमता को बढ़ाना है।